शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 47 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक – 46 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 14 – 21 नवम्बर 2022 मूल्य पांच रूपए

कौन होगा कांग्रेस में मुख्यमंत्री अटकलों का बाजार हुआ गर्म

क्या नेतृत्व की रेस में अहम टकरायेगे? क्या वरियता को अधिमान मिलेगा?

शिमला/शैल। कौन होगा कांग्रेस में अगला मुख्यमंत्री प्रशासनिक गलियारों से लेकर राजनीतिक दलों के कार्यालयों तक में यह सवाल इन दिनों सबसे अधिक अटकलों का केन्द्र

बना हुआ है। क्योंकि प्रशासन के शीर्ष पर बैठे जिन अधिकारियों के पास दिन में दो-दो बार फील्ड से फीडबैक आता है उनके एक बड़े वर्ग ने कांग्रेस के सम्भावित मुख्यमन्त्रीयों के यहां दस्तक देना शुरू कर दिया है। चर्चा है कि जयराम सरकार में जिस अधिकारी ने मुख्य सचिव के पद तक सात अधिकारियों को पहुंचा कर प्रशासनिक स्थिरता की बलि ले ली और मुख्यमन्त्री को इस बारे में सचेत तक होने का अवसर नहीं दिया उसी अधिकारी ने अपने पयादो के साथ यह खेल खेलना शुरू कर दिया है। चर्चा तो यहां तक है कि इनकी हाजिरी का प्रमाण किसी ने फोटो के साथ जयराम को भी भेज दिया। यह फोटो देखकर जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया क्या रही होगी इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। यह एक स्थापित सच है कि जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे उसे छोड़ कर भागना शुरू करते हैं। सत्ता परिवर्तन के यह अच्छे संकेत हैं। लेकिन इन्हीं संकेतों का दूसरा पक्ष उतना ही गंभीर है। क्योंकि भाजपा में इन चुनावों के लिए जयराम से ज्यादा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठाएं दांव पर लगी हुई है। गैर भाजपा शासित कितने राज्यों में ऑपरेशन लोटस चलाकर सरकारें गिराने के प्रयास हो चुके हैं यह पूरा देश जानता है। ऐसे में जहां अभी चुनाव

चल रहे हैं उन राज्यों में सत्ता के लिए भाजपा किसी भी हद तक जाने का प्रयास कर सकती हैं इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतदान और मतगणना के बीच रखा गया लम्बा अन्तराल कई आशंकाओं की ओर संकेत करता है। रामपुर और घुमारवीं में ईवीएम मशीनों को लेकर सामने आई आशंकाओं को यदि कांग्रेस का आधारहीन डर भी मान लिया जाये तो ऊना में चुनाव आयोग को इन मशीनों की पहरेदारी के लिए स्वयं टैन्ट लगाकर क्यों बैठना पड़ा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद चुनाव आयोग के पास भी नहीं है।

इस परिदृश्य में जब कांग्रेस

के अन्दर यह सवाल उठा ही दिया गया है कि उसका

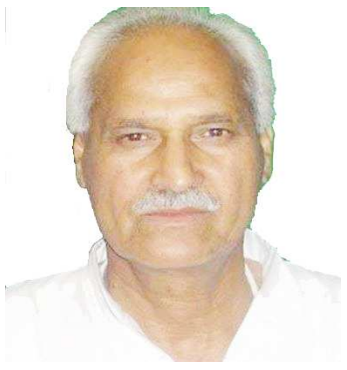

मुख्यमन्त्री कौन होगा तब यह भी साथ ही याद रखना होगा कि नेतृत्व का यह सवाल स्वयं प्रधानमन्त्री तक कांग्रेस पर दाग चुके हैं। उससे यह संकेत स्पष्टत: उभरते हैं कि आने वाले दिनों में नेतृत्व के प्रशन को आन्तरिक विरोधाभासों को उभारने का एक बड़ा माध्यम बनाया जाएगा। क्योंकि अभी प्रदेश कांग्रेस में स्थापित नेतृत्व उभरने में समय लगेगा। वर्तमान में कांग्रेस के अन्दर अभी ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है जो अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर भी अपना वोट किसी के पक्ष में ट्रांसफर करने की बूकत रखता हो। विश्लेषकों की नजर में इसी के कारण कांग्रेस के दो विधायक और दो कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी छोड़कर भाजपा में गये हैं। इसी के साथ एक सच यह भी है कि कांग्रेस को उपचुनाव से लेकर इन आम चुनाव तक स्व. वीरभद्र सिंह के प्रति जनता के प्यार और सहानुभूति का भरपूर लाभ मिला है। प्रतिभा सिंह को इन परिस्थितियों में पार्टी का अध्यक्ष बनाना भी एक सही फैसला रहा

है। क्योंकि प्रतिभा सिंह के कारण ही वीरभद्र सिंह के विश्वस्त रहे सेवानिवृत्त अधिकारियों और दूसरे लोगों ने चुनाव के दौरान पार्टी कार्यालय को संभाल लिया। कांग्रेस जो आरोप पत्र नहीं ला पायी थी उसे इन्हीं लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान जनता तक पहुंचाया। भाजपा शायद यह मानकर चल रही थी कि जब उसने नेता प्रतिपक्ष और चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन को प्रधानमन्त्री और गृहमन्त्री की रैलियां रखवाकर उनके चुनाव क्षेत्रों में ही बांध कर रख दिया तो इसका सीधा असर कांग्रेस कार्यालय पर पड़ेगा। लेकिन वीरभद्र के विश्वस्त रहे इन अधिकारियों ने संगठन के पदाधिकारी हुए बिना ही कार्यालय को संभाल कर भाजपा की रणनीति पर ग्रहण लगा दिया। इसी प्रबन्धन के दम पर प्रतिभा

सिंह पैंतालीस और विक्रमादित्य, मुकेश और सुक्खु दस-ग्यारह रैलियां विभिन्न क्षेत्रों में कर पाये।

यह सही है कि भाजपा के मुकाबले कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर था। धनबल में भी कांग्रेस भाजपा के बराबर नहीं थी। लेकिन जनता जिस कदर महंगाई और बेरोजगारी से पीड़ित थी उसके चलते जनता सत्ता परिवर्तन के लिए मन बना चुकी थी। ऐसे में कांग्रेस को जनसमर्थन मिलने जा रहा है वह जनता का रोष पोषित विश्वास है। इस विश्वास को यदि कोई भी मुख्यमन्त्री होने के अहम में कमजोर करने का प्रयास करेगा उसे जनता बर्दाशत नहीं करेगी। स्व. वीरभद्र के प्रति जनता की सहानुभूति का लाभ अब के बाद नहीं मिलेगा। ऐसे में यदि विधायकों के बहुमत को नजरअंदाज करके मुख्यमन्त्री थोपने का प्रयास किया जायेगा तो उसके परिणाम घातक होंगे। क्योंकि कांग्रेस के पास अनुभवी विधायकों की लम्बी लाइन उपलब्ध रहेगी ऐसा माना जा रहा है।

राज्यपाल ने धर्मशाला के सराह में आयोजित धन्यवाद दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने तोंग लेन चैरिटेबल ट्रस्ट के 19वें धन्यवाद दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि ट्रस्ट के प्रयास और उसके परिणाम पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायी हैं।

उन्होंने कहा कि ट्रस्ट ने एक उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत किया है जो आज दूसरों को प्रेरित करने का कार्य कर रहा है। यह कार्यक्रम कांगड़ा जिले के धर्मशाला के सराह गांव में आयोजित किया गया।

राज्यपाल ने लामा जामयंग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके वर्षों की तपस्या का फल देखकर अत्यंत खुशी हो रही है। उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को व्यावहारिक रूप में कार्यान्वित कर समाज के कमजोर वर्ग के हजारों बच्चों के भविष्य को बदला है। उन्होंने कहा कि भिक्षुक ने गंभीर कुपोषण के शिकार 100 से अधिक बच्चों को बचाकर उन्हें जीवनदान दिया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ उन्हें भारतीय मूल्यों से भी जोड़ा जा रहा है।

आर्लेकर ने कहा कि इस प्रकार की समाजसेवी संस्थाओं को सहयोग देने की आवश्यकता है क्योंकि ये समाज के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रही हैं। उन्होंने प्राचीन भारतीय गुरुकुल प्रणाली की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इस दिशा में सोचने की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हमें अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को अपनाने की आवश्यकता है। हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए और देश के प्रति समर्पण भाव से कार्य करना चाहिए।

राज्यपाल ने उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए राकेश कुमार प्रजापति, विनोद आचार्य और साधना नेपाली को और तीन संगठनों को प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने छात्रावास परिसर का भी दौरा किया और परिसर में दी जा रही सुविधाओं का जायजा भी लिया।

इस अवसर पर भिक्षु जामयंग ने राज्यपाल का स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे धर्मगुरु दलाईलामा की शिक्षाओं को प्रचारित करने और प्राचीन भारतीय ज्ञान के पुनरोद्धार के लिए कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बहुत कम छात्रों के साथ यह संस्थान शुरू किया गया था और वर्तमान में यहां 300 से अधिक कमजोर वर्गों के छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत और भारतवासियों के सहयोग के लिए आभारी हैं।

इस कार्यक्रम में भाग ले रहे पद्मश्री डॉ. उमेश भारती ने ट्रस्ट से जुड़े अपने संस्मरणों को साझा करते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों से वे ट्रस्ट से जुड़कर समाज के गरीब, कमजोर और उपेक्षित बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने झुग्गी-झोपड़ियों में जाकर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो काम किया, वह बौद्ध भिक्षु जामयंग की प्रेरणा का ही परिणाम है।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रो. अजय श्रीवास्तव ने बताया कि संस्था ने 2018 में स्कूल परियोजना का कार्य शुरू किया था और आज यहां 346 बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग हर साल तोंग-लेन द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य और प्रयोगशाला सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

ब्रिटेन की प्रतिनिधि ब्रिगिड व्हीरिस्की ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, उपायुक्त कांगड़ा निपुण जिंदल और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

राज्य रेडक्रास सोसायटी ने किया दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव संजीव कुमार ने बताया कि सोसायटी द्वारा नाग देवता राम मंदिर अन्नाडेल शिमला में हिमाचल प्रदेश दंत चिकित्सालय शिमला के तत्वावधान में एक दिवसीय दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 लोगों के दांतों की जांच की गई। विभिन्न प्रकार की दंत चिकित्सा मोबाइल डेंटल वैन में प्रदान की गई।

उन्होंने शिविर के सफल आयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश दंत चिकित्सालय के प्रधानाचार्य डॉ. आशु गुप्ता एवं पब्लिक हैल्थ डेन्टस्ट्री के विभागाध्यक्ष डॉ. विनय भारद्वाज का आभार प्रकट व्यक्त किया। इस अवसर पर बच्चों को टूथब्रश भी वितरित किए गए। शिविर में डॉ. शैलजा वशिष्ट डॉ. अतुल सांख्यान, डॉ. नितिका व उनकी टीम के अतिरिक्त राज्य रेडक्रॉस अस्पताल अनुभाग की उपाध्यक्ष मधु सूद व मानद सचिव डॉ. किमी सूद और राज्य रेडक्रॉस के सदस्यों ने भाग लिया।

कड़े पहरे में हैं जिला के स्ट्रांग रूम:डॉ. निपुण जिंदल

शिमला/शैल। विधानसभा के आम चुनावों के बाद जिला कांगड़ा में स्थापित स्ट्रांग रूम सुरक्षा के कड़े पहरे में हैं। नगरोटा उपमंडल में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करते हुए उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने यह शब्द कहे। डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि जिला प्रशासन पूरी गंभीरता से चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन कर रहा है और प्रशासन द्वारा प्रत्येक स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किये गए हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा कर्मियों के अलावा सीसीटीवी के माध्यम से भी इनपर पूरी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिले के प्रशासनिक अधिकारी समय समय पर स्ट्रांग रूमों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने स्वयं नगरोटा में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को सर्तक रहकर अपनी सेवाएं देने के निर्देश दिए।

राज्यपाल ने संवेदना किट और नि:क्षय कार्यक्रम का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने धर्मशाला में जिला रेडक्रॉस सोसायटी कांगड़ा व जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में क्षयरोग (टीबी) अनाथ बच्चों के लिए संवेदना किट कार्यक्रम व कांगड़ा नि:क्षय किट कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने 100 अनाथ बच्चों के लिए शैक्षिक किट और रोगियों को 1000 नि:क्षय किट वितरित किए।

राज्यपाल ने जिला प्रशासन को शेष सभी टीबी रोगियों को 15 दिनों के भीतर गोद लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों में आम लोगों को शामिल कर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को अनुकूलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी कहा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य ने 2024 तक राज्य में टीबी के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इससे पहले, उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने जिले में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही नि:क्षय और संवेदना किट से संबंधित गतिविधियों और कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने नि:क्षय मित्र के साथ समय-समय पर हुए विचार-विमर्श और संवाद के बारे में भी अवगत कराया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. गुरदर्शन गुप्ता ने नि:क्षय मित्र के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 1321 टीबी रोगियों ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है, जिनमें से 564 को गोद लिया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि 121 को व्यक्तिगत रूप से अपनाया गया है।

साई एसोसिएशन, रोटरी क्लब और जिला रेडक्रॉस के प्रतिनिधि भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर धर्मशाला द्वारा एक दिवसीय वेबिनार आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय रीजनल सेंटर धर्मशाला में कंप्यूटर साइंस विभाग द्वारा एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें रिसोर्स पर्सन के तौर पर नारापुरेड्डी गंगाधर, ट्रेनर / सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑल्ट कैंपस प्राइवेट लिमिटेड धर्मशाला ने शिरकत की। वेबिनार में मुख्यातिथि रूप में रीजनल सेंटर धर्मशाला के डायरेक्टर डॉ. धर्म प्रकाश वर्मा शामिल हुए। इस वेबिनार में 70 छात्र और छात्राओं ने भाग लिया।

अपने संबोधन में डायरेक्टर डॉ. वर्मा ने वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा की कम्प्युटर का शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा की कम्प्युटर की मदद से विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों का काफी ज्ञान बढ़ा है तथा कम्प्यूटर इंजीनियर इस कार्य में दिन रात कठिन परिश्रम कर हर रोज नए आयाम जोड़ रहे हैं।

वेबिनार के रिसोर्स पर्सन नारापुरेडी गंगाधर ने बच्चों को वेब डेवलपमेंट के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया। उन्होंने इस एक दिवसीय वेबिनार में बच्चों को फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंतर्गत मोंगो डीबी, जावा स्क्रिप्ट, रियेक्ट, एचटीएमएल तथा सीएसएस, नेक्स्ट जेएसएस एवं वेरेसल की सहायता से लाइव वेबसाइट बनाने की तकनीकी जानकारी दी। इस वेबिनार के संयोजक सहायक प्रोफेसर सुखबीर सिंह व सह सयोजक सहायक प्रोफेसर रोहित कुमार वर्मा ने सभी कंप्यूटर इंजीनियर का आभार व्यक्त किया। इस वेबिनार के दौरान सहायक प्रोफेसर धीरज सौंखला, सहायक प्रोफेसर अदिति बधन, सहायक प्रोफेसर शिखा भी उपस्थित रहे ।

बीएड कॉलेज धर्मशाला में रिक्त सीटों हेतु 26 नवम्बर तक करें आवेदन

शिमला/शैल। राजकीय शिक्षा महाविद्यालय धर्मशाला की प्राचार्या आरती वर्मा ने बताया कि कॉलेज में बी.एड शैक्षिक सत्र 2022-24 के लिए कुछ श्रेणी वार सीटें ख़ाली हैं। उन्होंने बताया कि रिक्त सीटों के लिए 21 नवंबर से 26 नवंबर 2022 तक आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सीटें बीएड 2022 के एंट्रेंस टेस्ट के मेरिट के आधार पर भरी जाएंगी। इच्छुक अभ्यार्थी महाविद्यालय की वेबसाइट www.gctedharamsh ala.ac.in तथा दूरभाष संख्या 01892- 223140 पर संपर्क कर सकते हैं।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

अंजना

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्णः सुभासीष पन्डा

शिमला/शैल। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पर विचार-विमर्श सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर सूचना एवं जन संपर्क विभाग के प्रधान सचिव सुभासीष

पन्डा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। न्यूज़ वेबसाईट हिल पोस्ट के सम्पादक रविंद्र मखाईक और अमर उजाला के राज्य ब्यूरो प्रमुख सुरेश शांडिल्य कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे।

इस अवसर पर सुभासीष पन्डा ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई देते हुए मीडिया से नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना का और संचार करने तथा बेहतरी के लिए निरंतर सकारात्मक बदलाव लाने का आग्रह किया। उन्होने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका बहुत अहम है। वर्तमान में तकनीक के उपयोग के साथ सूचना सम्प्रेषण में सुविधा और साधनों की बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को सशद्र बनाने में मीडिया के विभिन्न माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मीडिया द्वारा उभारे गए सकारात्मक विषयों से हर व्यक्ति में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान मीडिया द्वारा सूचनाओं के सप्रेषण तथा नागरिकों में राष्ट्र की क्षमता पर विश्वास बनाए रखने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस दौर में मीडिया ने लोगों में राहत, भरोसे एवं विश्वसनीयता की भावना विकसित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई।

उन्होंने कहा कि बदलते परिदृश्य में मीडिया के समक्ष नई चुनौतियां भी सामने आई हैं और आधुनिकता एवं तकनीक के सही उपयोग के प्रति और अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज के सूचना एवं प्रौद्योगिकी के दौर में भी आपसी वार्तालाप उतना ही आवश्यक है क्योंकि इससे न केवल विचारों का आदान-प्रदान सुनिश्चित होता है बल्कि आपस में अधिक जुड़ाव भी महसूस होता है। उन्होंने कहा कि मीडिया हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाओं एवं देश के बारे में हमारी समझ एवं चिंतन को एक नई दिशा देता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के इस दौर में सूचना का प्रवाह बहुत बढ़ा है और सही सूचनाओं के संकलन में सकारात्मक सोच के साथ सचेत रहने की भी आवश्यकता है। उन्होंने मीडिया का राष्ट्र को एकजुट, सशक्त एवं प्रभावी बनाने में अपनी सार्थक भूमिका निभाने का भी आहवान किया।

रविंद्र मखाईक ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान में मीडिया संचालन के साधनों में बढ़ोत्तरी हुई है। संसाधनों के वैश्वीकरण के साथ राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका और अहम हो गई है। उन्होंने विभिन्न देशों में मीडिया की दिशा और दशा पर प्रकाश डालते हुए कोविड काल के दौरान दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के मीडिया में भारत के प्रति दृष्टिकोण पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मीडिया के संसाधनों में निरंतर आ रहे बदलाव सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में देश की सकारात्मक छवि बनाने में मीडिया सार्थक भूमिका निभा सकता है।

उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक ढांचे से किसी राष्ट्र का निर्माण होता है और मीडिया स्वतंत्रता काल से लेकर वर्तमान तक राष्ट्र की छवि से लेकर राष्ट्र निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाता आया है। उन्होंने कहा कि देश में घटित होने वाली सकारात्मक एवं नकारात्मक घटनाओं को प्रमुखता से सामने लाना मीडिया का दायित्व है, वहीं विश्व में देश की सकारात्मक एवं प्रभावशाली छवि निर्मित करने के दृष्टिगत प्रस्तुतिकरण में और अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। देश में हो रहे नवोन्मेषी प्रयासों को प्रमुखता प्रदान कर विश्व पटल पर हम भारत की और सशक्त छवि प्रस्तुत कर सकते हैं।

सुरेश शांडिल्य ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता आन्दोलन से लेकर वर्तमान तक राष्ट्र निर्माण में मीडिया के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के प्रति जन चेतना जगाने में मीडिया का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चार स्तम्भों में मीडिया को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्होंने कहा कि प्रेस की गरिमा और इसकी स्वतंत्रता कायम रखने के उद्देश्य से प्रेस परिषद का गठन किया गया था। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर प्रेस परिषद की ओर से प्रदत्त विषयों पर चर्चा के माध्यम से मीडिया कर्मियों को भी आत्मविवेचन का अवसर प्राप्त होता है।

उन्होंने कहा कि मीडिया के विभिन्न माध्यमों से सूचना सम्प्रेषण की रफ्तार में तेजी आ रही है। मीडिया समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए निरंतर प्रयास कर राष्ट्र निर्माण के तत्वों को पोषित कर रहा है। उन्होंने कहा कि मीडिया केवल मात्र सूचनाएं देने तक सीमित नहीं है अपितु साहित्य से भी इसका गहरा संबंध है। साहित्य व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है और इससे शब्दों के चयन सहित विषय की समझ में गहराई आती है। उन्होंने कहा कि मानवीय सरोकारों को प्रमुखता मिले तभी राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका सार्थक हो सकती है। समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की बेहतरी के लिए किए गए प्रयास राष्ट्र निर्माण के लिए अहम हैं। उन्होंने कहा कि अन्तिम व्यक्ति की आवाज़ मीडिया की आवाज़ बनकर सरकार व प्रशासन तक पहुंचे और उनका उत्थान ही हमारा ध्येय होना चाहिए।

इससे पूर्व निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क कमल कांत सरोच ने कार्यक्रम के मुख्य वक्ताओं का शॉल व टोपी भेंट कर स्वागत किया। उन्होंने मुख्य अतिथि व अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए राष्ट्रीय प्रेस दिवस के महत्व और अन्य विषयों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बेहतर समाज के निर्माण में मीडिया का अहम योगदान होता है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किए गए प्रयास राष्ट्र निर्माण में और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया किसी भी देश या समाज की वास्तविक स्थिति को रेखांकित करता है। सामाजिक घटनाओं और परिस्थितियों पर कड़ी नज़र रखने के साथ-साथ मीडिया सरकार एवं जनता के बीच एक अभिन्न कड़ी के रूप में कार्य करता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का उद्देश्य केवल सूचनाएं प्रदान करना ही नहीं है बल्कि इससे कहीं अधिक जन चेतना का सृजन करना भी है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका के निर्वहन का आहवान करते हुए कहा कि देश और समाज के निर्माण तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण एवं सार्थक है।

विचार-विमर्श सत्र के उपरांत संवाद सत्र का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त निदेशक सूचना एवं जन संपर्क आरती गुप्ता, संयुक्त निदेशक प्रदीप कंवर, विभिन्न मीडिया संस्थानों के संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि और सूचना एवं जन संपर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकार जगत को बधाई:प्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकार जगत को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जहां वह किसी भी सरकार के आंख, कान के रूप में आम लोगों व सरकार के बीच एक कड़ी के तौर पर कार्य करता है। अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए पत्रकार जगत बधाई का पात्र है।

प्रतिभा सिंह ने कहा है कि आधुनिक युग में बढ़ते सूचना प्रौद्योगिकी में पत्रकारिता में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले जहां पत्रकारिता का माध्यम केवल अखबार, रेडियो व दूरदर्शन ही प्रमुख थे, आज मोबाईल फोन की बजह से सोशल मीडिया भी प्रेस का प्रमुख माध्यम बन गया है जिस के चलते दुनिया या देश की किसी भी घटना की सूचना तुरंत ही पलभर में आम लोगों को मिल जाती है।

प्रतिभा सिंह ने मीडिया पर सरकारी तंत्र के बढ़ते दबाव पर चिंता व्यक्त की और कहा है कि इसे किसी भी सरकारी दबाव से मुक्त करने की बहुत ही आवश्यकता है। उन्होंने पत्रकारों का आहवान किया है कि उन्हें समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का सही ढंग से निर्वहन करते हुए सरकार की कमियों को उजागर करने व जन कल्याण कार्यो को भी प्रमुखता देनी चाहिए।

हिमाचल प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया

शिमला/शैल। भारत सरकार ने वर्ष 2021 से जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी 'बिरसा मुंडा' की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का

निर्णय लिया है। बिरसा मुंडा न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी, बल्कि समाज सुधारक थे जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार की शोषणकारी व्यवस्थाओं के खिलाफ उलगुलान (विद्रोह) जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हें धरती अब्बा के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने जनजातीय लोगों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों को समझने और एकता का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया था।

जनजातीय गौरव दिवस पूरे अनुसूचित क्षेत्रों में देशभक्ति के उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, जनजातीय गीत व नृत्य एवं चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

इस उपलक्ष्य में भरमौर में पट्टी से चौरासी परगना तक एक रैली आयोजित की गई। इस मौके पर सरकारी कर्मचारियों, स्वयं-सहायता समूहों, स्कूली बच्चों, महिला मंडलों आदि ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया और पारंपरिक पोशाकों, आभूषण पहन कर जनजातीय संस्कृति की आकर्षक आभा प्रस्तुत की। चौरासी परगना पहुंचने के बाद महिलाओं द्वारा आकर्षक जनजातीय नृत्य भी किया गया।

पांगी क्षेत्र में पारंपरिक जीवन शैली, स्वदेशी कृषि पद्धतियों को प्रदर्शित करती झाँकियां और फुलयात्रा, जोकारू इत्यादि मुख्य आकर्षण रहे। इस कार्यक्रम में लगभग 300 लोगों ने पारंपरिक परिधान पहनकर भाग लिया।

लाहौल-स्पीति जिले में स्कूलों में वाद-विवाद प्रतियोगिताएं, नारे, पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण रहीं। केलांग में लगभग 150 लोग एकत्रित हुए और शहर के बाजार में शोभा यात्रा निकाली गई। काजा में स्वच्छता अभियान और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जनजातीय नेताओं के योगदान व जीवनी पर प्रकाश डाला गया।

गद्दी नृत्य को मिली राष्ट्रीय स्तर पर पहचान

शिमला/शैल। उपायुक्त डीसी राणा ने उपायुक्त कार्यालय के परिसर में रायपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव

में हिमाचल प्रदेश के गद्दी नृत्य को तीसरा स्थान मिलने पर सरस्वती लोक कला संगम चंबा के कलाकारों को बधाई दी।

इस अवसर पर उन्होंने सांस्कृतिक दल को बधाई देते हुए कहा कि हिमाचल के लिए बड़ी गौरव की बात है कि चंबा जिला के गद्दी नृत्य को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। उन्होंने सांस्कृतिक दल को भविष्य में अपनी प्रतिभा को और निखारने के लिए भी कहा । उन्होंने कहा कि तृतीय स्थान पर रहे नृत्य पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए की धनराशि भी दी गई है।

जिला भाषा अधिकारी तुकेश शर्मा ने भी चंबा पहुंचने पर सांस्कृतिक दल का प्रोत्साहन बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक दल में अतुल शर्मा, हिमांशु, रमेश कुमार, कर्म चंद, उत्तम, विनोद, नीरज, विवेक, तिलक, टेकचंद, नरेश, संजय, नीलम, मिनाक्षी, पिंकी, अनीता, रेखा, वंदना कलाकार शामिल रहे।

गौरतलब है कि रायपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव के तहत आयोजित प्रतियोगिता में फसल कटाई की श्रेणी में छत्तीसगढ़ के 'करमा नृत्य' को प्रथम, ओडिशा के 'ढेंगसा नृत्य' को दूसरा और हिमाचल प्रदेश के 'गद्दी नृत्य' को तीसरा स्थान मिला। प्रतियोगिता में लगभग देश के 52 सांस्कृतिक दलों के प्रतिभागियों ने ने भाग लिया तथा अपने-अपने क्षेत्र की संस्कृति की झलक प्रस्तुत की।इस अवसर पर जिला लोक संपर्क अधिकारी सुभाष कटोच भी मौजूद रहे।

विश्व के सभी धर्म, भले ही और चीजों में अंतर रखते हों, लेकिन सभी इस बात पर एकमत हैं कि दुनिया में कुछ नहीं बस सत्य जीवित रहता है। .....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका–कुछ सवाल

किसी भी राष्ट्र के आधार उसकी कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका और न्यायपालिका माने जाते हैं। राष्ट्र की व्यवस्था चाहे लोकतांत्रिक हो या राजशाही हो इन आधारों का सीधा रिश्ता राष्ट्र के जनमानस से होता है। मीडिया इन आधारों और जनता के बीच एक सशक्त माध्यम के रूप में मौजूद रहता है। राष्ट्र की व्यवस्था चाहे जैसी भी हो उसका अन्तिम प्रतिफल जनता का व्यापक हित होता है। क्योंकि जब यह हित किन्हीं कारणों से आहत होता है तो व्यवस्था को लेकर व्यवधान और सवाल दोनों एक साथ पैदा होते हैं। यही व्यवधान राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया बनते हैं। यहीं से मीडिया की भूमिका का आकलन शुरू हो जाता है। यह देखा जाता है कि मीडिया किसकी पक्षधरता निभा रहा है। यह पक्षधरता ही इस निर्माण में उसकी भूमिका तय करती है। इस परिपेक्ष में जब भारत के संद्धर्भ में चिन्तन और चर्चा आती है तब सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ध्यान आकर्षित होता है। लोकतन्त्र में विपक्ष और सत्तापक्ष आवश्यक सोपान हैं। लेकिन जब सत्ता पक्ष विपक्ष से मुक्त व्यवस्था की कामना करता हुआ व्यवहारिक तौर पर ही विपक्ष को रास्ते से हटाने के सक्रिय प्रयासों में लग जाता है तो वहीं से लोकतन्त्र पर पहला ग्रहण लग जाता है। विपक्ष को हटाने के लिये जब धर्म को भी राजनीति का अभिन्न अंग बनाकर एक सामाजिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाता है तो उसकी कीमत आने वाली कई पीढ़ियों को चुकानी पड़ जाती हैं।

आज देश की जो स्थिति निर्मित होती जा रही हैं उसमें पहली बार लोकतन्त्र के स्थायी आधारों पर गंभीर सवाल उठते जा रहे हैं। कार्यपालिका को जो स्थायी चरित्र दिया गया था उस पर स्वयं सत्ता पक्ष द्वारा सवाल उठाते हुए उसमें कॉरपोरेट घरानों के नौकरशाहों को कार्यपालिका में जगह दी जा रही है। इसमें रोचक यह है कि इस पर किसी भी मंच पर कोई सार्वजनिक विचार–विमर्श तक नहीं हुआ है। कार्यपालिका का स्टील फ्रेम मानी जाने वाली अखिल भारतीय सेवा संवर्ग ने इसे सिर झुका कर स्वीकार कर लिया है। इसी स्वीकार का परिणाम है कि ईडी, आयकर और सीबीआई जैसी संस्थाओं पर राजनीतिक दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं। व्यवस्था पालिका में संसद से लेकर विधानसभाओं तक में हर बार आपराधिक छवि के माननीयों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। संसद और विधानसभाओं को अपराधियों से मुक्त करवाने के सारे दावे जुमले सिद्ध हुए हैं। अब तो न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी गंभीर आक्षेप लगने शुरू हो गये हैं। यह शुरुआत स्वयं देश के कानून मन्त्री ने की है। जब लोकतन्त्र के इन आधारों पर ही इस तरह के गंभीर आरोप लगने शुरू हो जायें तो क्या यह सोचना नहीं पड़ेगा कि वह आम आदमी इस व्यवस्था में कहां खड़ा है जिसके नाम पर यह सब किया जा रहा है।

आम आदमी के हित की व्याख्या जब शीर्ष पर बैठे कुछ संपन्न लोग करने लग जाते हैं तब सारी व्यवस्थायें एक–एक करके धराशायी होती चली जाती हैं। बड़ी चालाकी से इसे भविष्य के निर्माण की संज्ञा दे दी जाती है। नोटबन्दी और लॉकडउन के समय श्रम कानूनों में हुए संशोधन तथा विवादित कृषि कानून इसी निर्माण के नाम पर लाये गये थे। इन सारे सवालों पर जब मीडिया ने सत्ता पक्ष की पक्षधरता के साथ खड़े होने का फैसला ले लिया तो क्या उसी से राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका स्पष्ट नहीं हो जाती है। आज जब मीडिया सत्ता पक्ष के प्रचारक की भूमिका में आ खड़ा हो गया है तो उससे किस तरह की भूमिका की अपेक्षा की जा सकती है। इसी कारण से आज निष्पक्ष मीडिया को देशद्रोह और सरकारी विज्ञापनों पर रोक जैसे हथियारों से केन्द्र से लेकर राज्यों तक की सरकारें प्रताड़ित करने के प्रयासों में लगे हुए हैं। इस हमाम में सत्तापक्ष से लेकर विपक्ष तक की सारी सरकारें बराबर की नंगी हैं। इस परिदृश्य में राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका पर चर्चा करना एक प्रशासनिक औपचारिकता से अधिक कुछ नहीं रह जाता है।

हेट स्पीच:सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष का प्रमाण

गौतम चौधरी

राजनीतिक हलकों में हाल के वर्षो में हेट स्पीच यानी अभद्र भाषा एक खास प्रकार का आदर्श बन गया है। दरअसल, इसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए कुछ लोग जायज ठहराने लगे हैं लेकिन यह किसी कीमत पर सही नहीं है। वास्तविकता यह है कि यह उस समुदाय के अस्तित्व की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है जिसको लक्ष्य कर अभिव्यक्त किया जाता है। आजकल हेट स्पीच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों पर समाचार बहस का हिस्सा बन गया है। समाचार माध्यमों के विभिन्न वाहिनियों पर जानबूझकर हिंदू–मुस्लिम को एक–दूसरे के खिलाफ अंतहीन युद्ध के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसका कोई संभावित समाधान संभव ही नहीं है। हालांकि, ये समाचार वाहिनियों पर बहस करवाने और करने वाले भूल जाते हैं कि भारतीय संविधान समानता के सिद्धांत को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है एवं प्रत्येक को बंधुत्व के बंधन में बांधे रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।

जब हम हेट स्पीच वाली बहसों पर नजर दौडाते हैं तो हमारे सामने कई प्रश्न खड़े होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा सवाल क्या सचमुच दोनों समुदाय एक–दूसरे को नष्ट करने के लिए तत्पर हैं? सच पूछिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तविकता यह है कि इतिहास की पुनर्व्याख्या और घृणास्पद भाषणों के माध्यम से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को सही ठहराने की कोशिश मात्र की जा रही है। नफरत की इस राजनीति में, धर्म दूसरे के विमर्श को वैधता प्रदान करने के लिए एक लामबंद करने वाला उपकरण बन जाता है। धार्मिक नेता भी इस नकारात्मक अभियान का हिस्सा बन जाते हैं, विभाजनकारी बयान देते हैं, जो ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति को हवा देता है। फिलहाल के दिनों में जो राजनीतिक और समाजिक स्तर पर विभाजनकारी बयान देने और समाज को ध्रुविकृत करने की कोशिश कर रहे हैं उनके उपर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लगाम लगाने की कोशिश की है। विगत दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने इस प्रकार के विभाजनकारी बयानों पर न केवल गंभीर टिप्पणी की अपितु तीन प्रदेश की पुलिस को सख्त लहजे में हिदायत दी कि तय किए गए समय के बीच हेट स्पीच देने वालों के मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो उसे न्यायालय की अवमानना समझी जाएगी। मसलन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नफरत भरे भाषणों के खिलाफ दाखिल किए गए एक याचिका पर अपनी टिप्पणी में कहा कि यह देश के भविष्य के लिए और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरनाक है।

सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने कहा कि भारत का संविधान नागरिकों के बीच एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और बंधुत्व की परिकल्पना प्रस्तुत करता है, जो व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देता है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों को इसके खिलाफ तत्काल कारवाई करने का आदेश दिया। जिस दिन माननीय न्यायालय ने नफरत फैलाने वाले भाषणों के नियमन के लिए दिशानिर्देश स्थापित करने के लिए न्यायालय से अनुरोध करने वाली कुल ग्यारह रिट याचिकाओं की पीठ द्वारा सुनवाई की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने समाचार वाहिनियों पर पर अनियंत्रित घृणास्पद भाषणों पर गंभीर चिंता व्यक्त की और यह टिप्पणी कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभद्र भाषा के खिलाफ सख्त नियमों की आवश्यकता पर जोर दिया है।

शीर्ष अदालत के फैसले का काफी महत्व है, क्योंकि यह देश में बढ़ते ध्रुवीकरण और नफरत की गति को रोकने के लिए एक मिसाल कायम करने की क्षमता रखता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल निहित स्वार्थ वाले लोग, जैसे राजनेता, नफरत की राजनीति से लाभान्वित होते हैं। सत्तारूढ़ के दिल में मंशा है कि राष्ट्र को अस्थिरता के खतरों से बचाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर भारत के अल्पसंख्यकों के संविधान में विश्वास को पुष्ट किया है। इसे सभी नफरत फैलाने वालों के लिए एक सबक और राष्ट्र प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा के रूप में देखा जाना चाहिए।

भारत–अमरीका "युद्धाभ्यास 2022" का उत्तराखंड में आयोजन

शिमला। भारत–अमरीका संयुक्त प्रशिक्षण (युद्धाभ्यास–22) के 18वें संस्करण का आयोजन इस माह उत्तराखंड में किया जाएगा। यह युद्धाभ्यास भारत और अमरीका की सेनाओं की उत्कृष्ट पद्धतियों, कौशलों, तकनीकों और प्रक्रियाओं का आदान–प्रदान करने के लिए वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। युद्धाभ्यास के पिछले संस्करण का आयोजन अक्तूबर 2021 में अमरीका के अलास्का में ज्वाइंट बेस एलमेन्ड्राफ रिचर्डसन में किया गया था।

इस अभ्यास में अमरीकी सेना की 11वीं एयरबॉर्न डिवीजन की सेकेंड बिग्रेड के जवान और भारतीय सेना की असम रेजीमेंट के जवान भाग लेंगे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम संयुद्र राष्ट्र अधिदेश के चैप्टर–7 के अंतर्गत एकीकृत युद्धक समूह में नियोजन पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत शांति रक्षण और शांति लागू करने से संबंधित सभी प्रकार की कारवाइयां शामिल होंगी। दोनों देशों के सैनिक साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। संयुक्त अभ्यास के दौरान मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (एचएडीआर) कारवाइयों पर भी ध्यान दिया जाएगा। दोनों देशों की सेनाओं के जवान किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा में त्वरित और समन्वित रूप से राहत कार्य प्रारंभ करने का भी अभ्यास करेंगे।

दोनों सेनाओं के व्यावसायिक कौशलों और अनुभवों का पूरी तरह लाभ प्राप्त करने के लिए कमांड पोस्ट एक्सरसाइज और सावधानीपूर्वक चयन किए गए विषयों पर एक्सपर्ट एकेडमिक डिशक्शन (ईएडी) किए जाएंगे। फील्ड में प्रशिक्षण अभ्यास के अंतर्गत एकीकृत युद्ध समूहों का सत्यापन, फोर्स मल्टीप्लायर्स, निगरानी ग्रिड की स्थापना और कामकाज, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स का सत्यापन, पर्वतीय युद्ध कौशल, दुर्गम इलाके और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से घिरने पर आकस्मिक निकासी और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। इस प्रशिक्षण के दौरान युद्धक इंजीनियरिंग, यूएएस/काउंटर यूएएस तकनीकों का नियोजन और सूचना संचालन सहित युद्ध कौशल के व्यापक स्पेक्ट्रम पर आदान–प्रदान और अभ्यास शामिल होंगे।

यह युद्धाभ्यास दोनों देशों की सेनाओं को अपने व्यापक अनुभवों, कौशलों को साझा करने तथा सूचना के आदान–प्रदान से अपनी तकनीकों को संवर्धित करने का अवसर प्रदान करेगा।

मानगढ़ धाम की गौरव गाथा का स्मरण

अर्जुन राम मेघवाल
केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री, एवं बीकानेर से लोकसभा सांसद

हमारा देश हमारे गौरवान्वित नागरिकों के संपूर्ण सामर्थ्य का उपयोग करते हुए बहुआयामी रूप से विकास की राह पर बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव स्वयं का विश्लेषण करने और जन चेतना को जागृत करने का सही अवसर है ताकि देश नई ऊंचाइयों को छू सके। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक ऐसी गाथाएं शामिल हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों की जागृत चेतना को दर्शाती है जो राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लेने वाले सभी वर्गों को समाहित करती हैं। यशवंचित विस्मृत वीरों और वीरांगनाओं ने मातृभूमि की गरिमा की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर, 15 नवम्बर को मनाए गए द्वितीय 'जनजातीय गौरव दिवस' में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के पराक्रम और साहसिक कृत्यों का पुनः स्मरण कराया गया। 17 नवम्बर का दिन अंग्रेज हुकूमत के अत्याचारों के विरुध लड़ते हुए गोविंद गुरु के नेतृत्व में जनजातीय व्यक्तियों द्वारा किए गए नरसंहार का स्मरण कराता है। राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में एक बंजारा परिवार में जन्मे गोविंद गुरु ने स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा को आत्मसात किया और वह सामाजिक – धार्मिक उत्थान के माध्यम से भील जनजातियों को एकजुट करने के लिए सक्रिय हो गए। भारतीय परम्परा और आदर्शो के सच्चे प्रतिपादक के रूप में उन्होंने 25 वर्ष की आयु में सन् 1883 में जनजातीय लोगों के बीच एकता और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए 'संप सभा' की स्थापना की। ये सामाजिक – आर्थिक कदम उसी समय उठाए गए जिस समय ब्रिटिशराज भारत से योजनाबद्ध तरीके से लूटपाट कर रहा था और स्थानीय और स्वदेशी लोगों के हितों के प्रति असंवेदनशील हो गया था। सन् 1903 के बाद से मानगढ़ पहाड़ी इस क्षेत्र के भील और अन्य जनजातीय लोगों के लिए एक मेले के रूप में आयोजित वार्षिक समागम के लिए प्रसिद्ध स्थान बन गया था। भारत में स्व – शासन की मांग ने 20वीं शताब्दी के पहले दशक में बहुत अधिक जोर पकड़ लिया। फूट डालो और राज करो की नीति और उसके परिणामस्वरूप हुए बंगाल विभाजन तथा धन संपत्ति को देश से बाहर ले जाने की प्रणाली ने ब्रिटिश शासन के नैतिक आधार का भांडाफोड़ कर दिया था। गोविंद गुरु ने भी सूखा/अकाल प्रभावित परिस्थितियों में जनजातियों से लिए जाने वाले लगान को कम करने और धर्म तथा रीति – रिवाजों का पालन करने में स्वतंत्रता की मांग रखी। स्वतंत्रता संग्राम के भाग के रूप में, जनजातियां और भील समुदाय अंग्रेजों के विरुध बड़े संघर्ष की तैयारी में जुटे थे। सन 1913 में 17 नवम्बर की पूर्णिमा के दिन मानगढ़ पहाड़ी पर 1.5 लाख से अधिक भील, गुरु के प्रति अपनी निष्ठा दर्शाते हुए इकटठा हुए ताकि वे अपनी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा कर सकें और ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कोई रास्ता खोज सकें। गैर कानूनी रूप से इकटठा किया गया लगान स्पष्ट रूप से अंग्रेजों की दमनकारी नीति और अन्यायपूर्ण कृत्यों को दर्शाता था। 'भूरेटिया नही मानू रे' में अंग्रेजों के दमनकारी शासन के प्रति कभी भी वफादार होना स्वीकार नहीं करूंगा गीत जनजातीय लोगों की मुखर अभिव्यक्ति बन गया। अतः अन्याय के विरुध लड़ने के लिए गोविंद गुरु का आहवान ब्रिटिश शासन के विरुध प्रथम सविनय अवज्ञा आन्दोलन की नींव साबित हुआ। इतने बड़े पैमाने पर होने वाली सभा की भनक लगते ही अंग्रेजों ने मानगढ़ पहाड़ी पर 7 कंपनियां तैनात की जिन्होंने पूरी मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया और तोपें भी तैनात कर दीं। गोलियों का भय दिखाते हुए जनजातीय लोगों के हौंसलों को पस्त करने का प्रयास किया। अंग्रेजी हुकूमत ने गोविन्द गुरू और उनके अनुयायी भील समाज के लोगों को मानगढ़ पहाड़ी खाली करने का आदेश दिया। जनता की आध्यात्मिकता द्वारा संवर्धित जागृत चेतना किसी भी प्रकार से अंग्रेजों के प्रति वफादारी स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उनके विश्वास और मातृभूमि की रक्षा करने की भावना ने गोलियों के भय को नजरअन्दाज कर दिया। संवेदनहीन अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर गोलीबारी का आदेश दिया और इस अमानवीय कृत्य के कारण उस दिन 1500 से अधिक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण त्याग दिए। अंग्रेजों का नैतिक आचरण लगातार विकृत होता गया जब उन्होंने 6 वर्षो के बाद जलियांवाला बाग नरसंहार और ऐसे ही अन्य अमानवीय कृत्यों को अंजाम दिया।

स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे विस्मृत वीरों के बलिदानों ने राष्ट्रवादी समुदाय के नैतिक मूल्यों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इससे स्वतंत्रता को कानूनी और न्यायसंगत आवश्यकता के रूप में देखे जाने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। इस भावना ने सभी को स्वतंत्र भारत के लिए कर्तव्यनिष्ठता से अपनी सक्रिय भूमिका निभाने में संपूर्ण रूप से प्रेरित किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमारे मूल, एकता और कर्तव्यपरायणता पर गर्व करते हुए औपनिवेशिक मानसिकता के अवशेषों को हटाते हुए विकसित भारत के उद्देश्य के साथ अमृत काल के पांच प्रण का आहवान किया है। राष्ट्र निर्माण हेतु स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीयों की महत्वपूर्ण भूमिका पूर्ण रूप से एक प्रेरणादायक गाथा है। जनजातीय संस्कृति, प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के प्रति उनकी संबधता और सौहार्द अनुकरणीय है तथा संभ्रांत वर्ग और विकसित देशों के लिए एक सबक है जिसके माध्यम से कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के तौर – तरीकों पर चर्चा की जा सकती है। हाल ही में 01 नवंबर को मानगढ़ पहाड़ी में आयोजित 'मानगढ़ धाम की गौरव गाथा' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों के साथ, गोविन्द गुरू व बलिदानी भील समाज के वीरों का श्रद्धांजलि देने उपस्थित हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1913 में इसी पहाड़ी पर एकत्रित जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। राष्ट्रीय जनजातीय केन्द्र के रूप में इसका विकास राष्ट्र निर्माण में जनजातीय योगदान को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर घोषणा की कि मानगढ़ धाम का विकास राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की सरकारों के समन्वित प्रयासों और सहयोग से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आदिवासी समाज के राष्ट्र निर्माण में योगदान एवं देश की स्वतंत्रता में उनके योगदान और बलिदान को रेखांकित करते हुए भारत सरकार द्वारा दस राज्यों यथा – अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा एवं केरल में जनजाति संग्रहालय विकसित किए जा रहे हैं।

भारत के विकास पथ की तुलना किसी भरे गिलास से करें तो जनजातीय विरासत का उल्लेख करना ऐसा ही होगा जैसे आधे भरे गिलास को उलट देना। अब मोदी सरकार द्वारा की गई पहलों से जनजातीय लोग सरकार की मुख्य धारा में विकास एजेंडा में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। इस गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में जनजातीय नेता द्रौपदी मुर्मू को पाकर राष्ट्र गौरवान्वित महसूस करता है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल परिषद भी 08 जनजातीय मंत्रियों से अंकित है। लक्षित लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाते हुए संपूर्ण परिपूर्णता करने के लिए गरीब कल्याण उपाय, जन केन्द्रित नीतियां और सुशासन के दृष्टिकोण ने उनके जीवनयापन को आसान करने की सुविधा प्रदान की है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण, आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना, छात्रों के लिए समर्पित छात्रवृत्ति स्कीम, सिकल सेल एनीमिया को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान, मिशन इन्द्रधनुष, अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से जनजातीय विकास, बांस को वृक्ष की परिभाषा से हटाना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य जनजातीय लोगों की क्षमता को विकसित करने में सहायता कर रहे हैं। संशोधनों के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण सुदृढ़ करने से उनके विरुध अत्याचारों का प्रभावी निवारण हुआ है। समग्र रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण सामाजिक न्याय की एक नई परिभाषा तैयार हो रही है। आज हम मानगढ़ के शहीदों और विस्मृत वीरों के उत्कृष्ट बलिदान को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आइए, समकालीन अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों पर एक व्यावहारिक समस्या – निवारक के रूप में, एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहे एक नए भारत के निर्माण हेतु उन स्वतंत्रता सेनानियों की नैतिकता के साथ हम अपने मूल्यों को एक साथ सार्थक करें। आइए, अपने अतीत को जानें, अदम्य विरासत को आगे बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ी के लिए एक उज्ज्वल भविष्य प्राप्त होने हेतु सांस्कृतिक मूल्यों से सीख प्राप्त करें। यह एक विकसित भारत के निर्माण के लिए सोच समझकर चिंतन – मनन करने और कार्य करने का समय है।

ग्रामीण भारत में विश्व शौचालय दिवस 2022 पर स्वच्छता दौड़' का आयोजन

शिमला। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) 19 नवंबर, 2022 को विश्व शौचालय दिवस के मौके पर ग्रामीण भारत में 'स्वच्छता दौड' का आयोजन कर रहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लोकल हीरोज, स्वच्छाग्रहियों, आशा कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों, युवाओं, स्कूली बच्चों और स्थानीय लोक कलाकारों आदि को शामिल करते हुए ग्राम पंचायत स्तर

पर 'स्वच्छता दौड' आयोजित करने का निर्देश दिया गया। स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों / स्थानीय लोक कलाकारों को भी इसमें शामिल करने का सुझाव दिया गया है। स्थानीय लोगों को भागीदारी के लिए उत्साहित करने के लिए खिलाड़ियों/ सेलेब्रिटीज/ स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा 'दौड़' को झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस दौड़ के प्रारंभ में सभी प्रतिभागियों द्वारा 'स्वच्छता प्रतिज्ञा' लेने(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण – II के बैनर, पोस्टर, स्लोगन और अन्य बाहरी सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री को मार्ग में प्रदर्शित करने, ऐतिहासिक महत्व के स्थल और/या पंचायत कार्यालय में 'दौड़' शुरू और समाप्त करने(रीफ्रेशमेंट, मेडिकल किट, टी – शर्ट और भागीदारी प्रमाण पत्र के प्रावधान का ग्राम पंचायत द्वारा ध्यान रखने के बारे में सूचित किया गया है।

कार्यक्रम के मुख्य बिंदु –

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को विश्व शौचालय दिवस, 2022 मनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 'स्वच्छता दौड़' आयोजित करने का निर्देश दिया।

विश्व शौचालय दिवस, 2022 के उपलक्ष्य में स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि/खिलाड़ी/सेलिब्रिटी/ प्रभावशाली लोग 'स्वच्छता दौड़' को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे

विश्व शौचालय दिवस 2013 से प्रतिवर्ष शौचालयों का जश्न मनाने और स्वच्छता तक पहुंच के बिना रहने वाले लोगों के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है

विश्व शौचालय दिवस 2022 की थीम है 'मेकिंग द इनविजिबल विजिबल'

यह दिवस वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए कारवाई पर प्रकाश डालने के बारे में है

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को दुनिया के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी गई है

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 'जल आंदोलन' ने ग्रामीण भारत की आबादी के जीवन को बदल दिया है

एनआईसी के साथ डीडीडब्ल्यूएस ने स्वच्छता दौड़ गतिविधियों की निगरानी के लिए एक समर्पित ई – मॉडयूल विकसित किया है। राज्य और केंद्र – शासित प्रदेश 'दौड़' के स्थान के बारे में जानकारी अपलोड करेंगे, गणमान्य व्यक्ति फ्लैगिंग/दौड़ में भाग लेंगे, प्रतिभागियों की संख्या और 'दौड' की तस्वीरें और घटना का संक्षिप्त विवरण भी जिलों से प्राप्त किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) आईईसी संचार सामग्री की एक सॉफ्टकॉपी, जिसमें 'दौड़' के बारे में अधिसूचना शामिल है, क्यूआर कोड के माध्यम से राज्यों को प्रदान की गई थी जिसे 17 नवंबर 22 को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ आयोजित एक प्रारंभिक वीडियो कॉन्फ्रेंस में साझा किया गया था।

2013 से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह वैश्विक आयोजन, शौचालयों का जश्न मनाता है और स्वच्छता तक पहुंच के बिना रहने वाले लोगों के लिए जागरूकता बढ़ाता है। 2022 की थीम 'मेकिंग द इनविजिबल विजिबल' है और यह पता लगाने का प्रयास करती है कि कैसे अपर्याप्त स्वच्छता प्रणालियां मानव अपशिष्ट को नदियों, झीलों और मिट्टी में फैलाती हैं और भूमिगत जल संसाधनों को प्रदूषित करती हैं। यह समस्या ऑश्य लगती है क्योंकि जल प्रदूषण भूमिगत होता है। यह विशेष दिन वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने और सतत विकास लक्ष्य 6.2: 2030 तक सभी के लिए स्वच्छता और पानी प्राप्त करने के लिए कार्यो को उजागर करने के बारे में है। भले ही भारत सुरक्षित स्वच्छता तक पहुंच से संबंधित एसजीसी लक्ष्य 6.2 पहले ही हासिल कर चुका है, जब देश ने अक्तूबर 2019 में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा हासिल किया(यह अब ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल करने के अपने प्रयासों में लगा हुआ है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को दुनिया के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी गई है। यह लोगों की भागीदारी के प्रभावशाली बल – 'जल आंदोलन' का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने सामाजिक लाभ, आर्थिक लाभ, पर्यावरण सुरक्षा और सबसे महत्वपूर्ण रूप से महिलाओं की गरिमा तथा सुरक्षा के मामले में ग्रामीण भारत की आबादी के जीवन को बदल दिया। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का दूसरा चरण स्वस्थ व्यवहार की इस मजबूत नींव पर ध्यान केंद्रित करता है और ओडीएफ प्लस की दिशा में सूचित, शिक्षित और कारवाई करता है। 'स्वच्छता दौड़' भी जनता को शामिल करने की एक ऐसी कारवाई है। 'दौड' का उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण II घटकों से जुड़े शौचालय, सुरक्षित स्वच्छता और दृश्य स्वच्छता के उपयोग के महत्व के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना है।

राज्यपाल ने धर्मगुरु दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कांगड़ा जिले के थेकचेन, मैकलोडगंज, धर्मशाला में गांधी मंडेला फाउंडेशन (जीएमएफ) द्वारा आयोजित एक ऐतिहासिक समारोह में धर्मगुरु दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया।

गांधी मंडेला फाउंडेशन वैश्विक शांति और स्वतंत्रता के हित में महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला के मूल्यों और आदर्शों को बढ़ावा देता रहा है। यह पुरस्कार उन वैश्विक नेताओं को सम्मानित करने का कार्य करता है जो नागरिकों को शांति, एकता और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करते हैं।

इस अवसर पर धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि अहिंसा और करुणा विश्व शांति के लिए आवश्यक हैं और ये दोनों सिद्धांत हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति में रचे-बसे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध में नहीं बल्कि बातचीत और शांति के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विश्व शांति के लिए हमें अहिंसा और करुणा का मार्ग अपनाना होगा। ये दोनों सिद्धांत मानव अस्तित्व की मार्गदर्शक शक्तियां हैं।

उन्होंने गांधी मंडेला पुरस्कार प्रदान करने के लिए फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया।

राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि धर्मगुरु दलाई लामा इस पुरस्कार के लिए योग्य व्यक्ति हैं क्योंकि वह शांति के सार्वभौमिक दूत हैं और इन्हें भारतीय संस्कृति और विचारों को आगे बढ़ाने के लिए सम्मानित किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि वह सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें दलाई लामा को सम्मानित करने का अवसर मिला।

आर्लेकर ने कहा कि दलाई लामा ने विश्व को अहिंसा और करुणा के सिद्धांत दिये हैं, जिनकी आज के समय में आवश्यकता है क्योंकि यह सेना की शक्ति से अधिक प्रभावी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में दूसरों के प्रति सद्भावना, करुणा और प्रेम की भावना है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसे आगे बढ़ाने का काम दलाई लामा ने किया है। उन्होंने गांधी मंडेला फाउंडेशन को बधाई देते हुए कहा कि दलाई लामा को यह पुरस्कार देकर उन्होंने हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति को सही मायने में आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला के बाद दलाई लामा जी में विश्व नागरिक बनने की क्षमता है क्योंकि वह सीमाओं से बंधे व्यक्ति नहीं हैं।

इससे पहले न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन, जूरी के अध्यक्ष और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा बड़े समुदाय के रक्षक हैं और युवा पीढ़ी को दलाई लामा की शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह महान नेता हैं और गांधी मंडेला पुरस्कार के लिए उन्हें चुनने पर फाउंडेशन ने खुद को सम्मानित महसूस किया। उन्होंने कहा कि वे कांगड़ा में पहली बार आए हैं। यह बहुत खूबसूरत है और वह बहुत उत्साहित हैं।

जूरी के उपाध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा ने कहा कि धर्मगुरु ने पूरे विश्व को शांति का मार्ग दिखाया है। विश्व में व्याप्त अशांति के दौर में दलाई लामा ने शांति का उपदेश दिया जो हमें यह बताता है कि शांति स्थापित करके सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है।

गांधी मंडेला फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम जाजू ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर जीएमएफ के महासचिव नंदन झा ने राज्यपाल का स्वागत किया।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव, राजेश शर्मा, कांगड़ा के उपायुक्त निपुण जिंदल तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर ने राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट कर उन्हें आयोग की वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

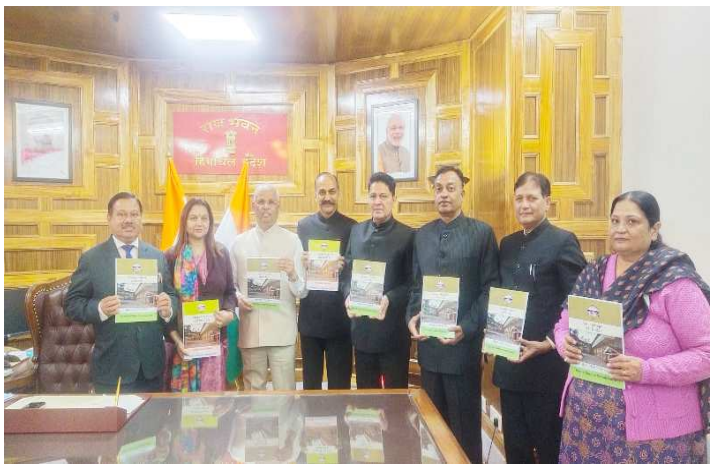

इस अवसर पर आयोग की सदस्य डॉ. रचना गुप्ता, राकेश शर्मा, कर्नल राजेश कुमार शर्मा, नैन सिंह और आयोग के सचिव देवेंद्र कुमार रतन भी उपस्थित थे।

ग्रामीण विकास गतिविधियों में नाबार्ड की भूमिका अहम

शिमला/शैल। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) हरियाणा के क्लस्टर अधिकारियों की चौथी बीएसएम डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में शुरू हुई। बैठक का उद्घाटन नौणी विवि के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने किया और इसमें हरियाणा में बैंक के जिला विकास प्रबंधकों ने भाग लिया।

अधिकारियों का स्वागत करते हुए प्रोफेसर चंदेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य संबद्ध आर्थिक गतिविधियों के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रवाह और अन्य हस्तक्षेपों को सुविधाजनक बनाने में नाबार्ड जैसे वित्तीय संस्थानों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थान बैंक के सहयोग से किसानों की आय बढ़ाने के लिए विकसित विभिन्न कृषि म डलों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे विश्वविद्यालय द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को बड़े स्तर पर बढ़ाने की संभावनाओं की तलाश करें। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि विश्वविद्यालय और नाबार्ड छात्रों और किसानों को अपना उद्यम और किसान उत्पादक कंपनियां शुरू करने के लिए ज्ञान देने के लिए एक अल्पकालिक पाठयक्रम शुरू करने की दिशा में काम कर सकते हैं।

नाबार्ड हरियाणा की सीजीएम दीपा बी गुहा ने इस अवसर पर कहा कि यह बैठक अधिकारियों के लिए क्रॉस-लर्निंग अभ्यास का हिस्सा है और इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में सक्षम बनाना होगा। उन्होंने कहा कि यह दौरा नवीनतम और नई आईओटी-आधारित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए बैंक द्वारा समर्थित हस्तक्षेपों का भी उल्लेख किया गया। चौपाल नैचुरलस एफ़पीसी के अध्यक्ष विनोद मेहता ने उनकी एफ़पीसी के बारे में एक प्रस्तुति दी। विश्वविद्यालय की पोस्ट हार्वेस्ट सुविधाओं, फ्लोरल क्राफ्ट लैब, कीटनाशक अवशेष प्रयोगशाला, टिश्यू कल्चर और वन उत्पाद प्रयोगशालाओं, प्राकृतिक खेती प्रायोगिक ब्लॉक, कीवी ब्लॉक, हाई-डेंसिटी सेब प्लांटेशन और हाई-टेक फ्लोरिकल्चर लैब का भी दौरा किया गया।

डॉ. संजीव चौहान, निदेशक अनुसंधान (डॉ. इंदर देव, निदेशक विस्तार शिक्षा, संदीप नेगी, रजिस्ट्रार, डॉ.सी. एल. ठाकुर, डीन कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री (डॉ.अंजू धीमान, लाइब्रेरियन, डॉ. माया देवी, जीएम हरियाणा, विनोद आर्य, जीएम हरियाणा, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधकों और चौपाल नैचुरलस एफ़पीसी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया।

डीसी कांगड़ा ने किया राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ

शिमला/शैल। उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने कांगड़ा उपमंडल के तहत राजकीय प्राथमिक विद्यालय तकीपुर में बच्चों को अल्बेंडाजोल की खुराक खिलाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. गुरदर्शन गुप्ता भी मौजूद रहे। बता दें कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य पर पूरे जिले में लगभग 3 लाख 80 हजार बच्चों को अल्बेंडाजोल की खुराक दी गई, वहीं करीब 1 लाख 22 हजार बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी गई।

डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का उद्देश्य बच्चों व किशारों का समग्र स्वास्थ्य तय बनाना है। इसमें 1-18 वर्ष की आयु के बीच के सभी पूर्वस्कूली और स्कूली उम्र के बच्चों को स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से उनके अच्छे स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए कृमि नाशक दवा दी जाती है। प्रशासन का प्रयास है कि शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक बच्चे को इस अभियान के तहत कवर किया जाए।

उन्होंने बताया कि बच्चों के पेट में कीड़े उत्पन्न होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। दूषित जल स्रोतों से पानी ग्रहण करना, मिट्टी में खेलना और बिना हाथ धोए भोजन करना, सब्जियों को बिना धोए या छीले अथवा असावधानी से पकाना, जैसे कारणों से पेट के कीड़ों की समस्या हो सकती है। इस संक्रमण से एनीमिया, कुपोषण तथा बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रयास किए जाते हैं।

डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि पेट के कीड़ों से बचने के लिए हमें बच्चों के जीवन में कुछ व्यवहारिक बदलाव करने आवश्यक हैं। उन्होंने बताया कि इसके संक्रमण को रोकने के लिए स्वच्छ शौचालयों का उपयोग करना, बाहर शौच नहीं करना, हाथों की स्वच्छता, विशेष रूप से खाने से पहले और शौचालय का उपयोग करने के बाद अच्छे से हाथ धोना, नंगे पांव न घूमना, फलों और सब्जियों को सुरक्षित और साफ पानी में धोना, ठीक से पका हुआ भोजन करना जैसे व्यवहारों को बच्चों की जीवनचर्या का अंग बनाना चाहिए।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि विटामिन ए की खुराक 5 साल तक के बच्चों को आंखों की बीमारियों से बचाव के लिए दी जाती है। वहीं अल्बेंडाजोल की खुराक 1 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को दी जाती है। उन्होंने बताया कि जो बच्चे दवाई की खुराक नहीं ले पाए, वह मॉपिंग अप वाले दिन इसे ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि छूटे हुए बच्चों को अल्बेंडाजोल की खुराक भी उस दिन दी जाएगी।

इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी डॉ. विक्रम कटोच तथा कार्यक्रम अधिकारी धर्मशाला डॉ वंदना मौजूद रहे।

राज्यपाल ने एकीकृत चिकित्सा शिक्षा पद्धति पर बल दिया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला के अटल सभागार में फैलोशिप ऑफ इण्डियन एसोसिएशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोसर्जन (एफआईएजीईएस) के तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर उन्होंने एकीकृत चिकित्सा शिक्षा पद्धति पर बल देते हुए कहा कि इसमें एलोपैथी के साथ-साथ होम्योपैथी और आयुर्वेद को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि आज के दौर में एलोपैथी के अलावा अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता है।

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि हमारी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली हजारों वर्ष पुरानी है, जो आधुनिक समय की उपचार तकनीकों को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। एकीकृत चिकित्सा पद्धति लोगों को बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने में सक्षम है। उन्होंने सभी विशेषज्ञों से इस दिशा में विचार करने और खुली चर्चा का आहवान किया। राज्यपाल ने कहा कि यहां उपस्थित प्रतिभागी अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और मुझे उम्मीद है कि इस तीन दिवसीय सम्मेलन में होने वाले विचार-विमर्श से नवोदित शल्य चिकित्सकों (सर्जन) को बहुत लाभ होगा जिससे वे आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर पाएंगे।

राज्यपाल ने एफआईएजीईएस के प्रयासों की सराहना करते हुए इस आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के दौरान आयोजित फेलोशिप कोर्स कई प्रतिनिधियों को लैप्रोस्कोपिक कौशल में प्रशिक्षित करेगा। उन्होंने कहा कि इन शैक्षणिक गतिविधियों और प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से सर्जन, विशेष रूप से युवा सर्जन नई तकनीक से अपने कौशल में निखार और अपने ज्ञान को बढ़ाकर लाभान्वित होंगे।

इससे पहले राज्यपाल का सम्मेलन में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया और उन्होंने एफआईएजीईएस की स्मारिका का विमोचन भी किया।

इंडियन एसोसिएशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोसर्जन (आईएजीईएस) के अध्यक्ष डॉ. एलपी थंगावेलु ने एसोसिएशन की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि आईएजीईएस भारत का एक प्रमुख संगठन है और विश्वभर में इसके दस हजार से अधिक सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि संघ द्वारा युवा सर्जनों के लिए विभिन्न ऑनलाइन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और नकद पुरस्कार प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में देश भर से सैकड़ों प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

इससे पूर्व डॉ. आरएस झोगटा ने राज्यपाल का स्वागत किया। इस अवसर पर निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं अटल अतिविशिष्ट चिकित्सा संस्थान, चमियाना, शिमला के प्रधानाचार्य प्रो. रजनीश पठानिया, प्रिंसिपल आईजीएमसी डॉ. सीता ठाकुर एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति और आईजीएमसी के कर्मचारी भी उपस्थित थे।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में इंदिरा गांधी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर याद करते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किये। इस अवसर पर पूर्व विधायक एवम प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष आदर्श सूद ने कहा कि प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर यह प्रदेश उनके इस ऋण से कभी मुक्त नही हो सकता। इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अंखडता के लिये अपने प्राणों कि आहुति तक दी, इसलिए उनका नाम सदा अमर रहेगा।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में इंदिरा गांधी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे विश्व में अपनी राजनीति का लोहा मनवाते हुए दृढ़ इच्छाशक्ति व संकल्प के चलते अपना नाम आर्यन लेडी के नाम से विख्यात करवाया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रहते इंदिरा गांधी ने अपनी विदेश नीति के चलते अन्य देशों में भारत का लोहा मनवाया। इंदिरा गांधी का विशेष लगाव प्रदेश से रहा। उन्होंने एक ओर जहां प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था, वही लाहुल स्पिति के लोगों की मांग पर रोहतांग दर्रे पर टनल के निर्माण को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि रोहतांग टनल कांग्रेस की देन है,यह प्रदेश सदैव उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस नेताओं का आहवान किया कि उन्हें देश व प्रदेश हित में पार्टी की मजबूती के लिये स्व. इंदिरा गांधी के दिखाये पथ का अनुसरण करना होगा, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होंगी।

स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत विषय पर संगोष्ठी आयोजित

शिमला/शैल। पब्लिक रिलेशन्ज़ सोसायटी ऑफ इंडिया (पीआरएसआई) के शिमला चैप्टर तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग ने संयुक्त तत्वावधान में आजादी का अमृत महोत्सव 'स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया।

इस अवसर पर विख्यात लेखिका एवं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डॉ. उषा बादे ने कहा कि भारत को स्वतंत्र करवाने में स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता है। उनके बलिदानों के परिणामस्वरूप ही आज राष्ट्र विश्व पटल पर अग्रणी देश बनकर उभरा है। उन्होंने अपने शोध पत्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझा करते हुए विभिन्न लेखकों द्वारा महात्मा गांधी पर लिखी गई किताबों पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि इन लेखकों की रचनाओं में बेशक महात्मा गांधी नहीं हैं, लेकिन उनकी विचारधारा सभी जगह व्याप्त है जो लोगों में देशभक्ति और देशप्रेम की भावना जागृत करती है। उन्होंने कहा कि विभिन्न भाषाओं के साहित्य में गांधी जी के सिद्धांतों को प्रमुखता प्रदान की गई है। उन्होंने नैन तारा सहगल, मुल्ख राज आनंद, भवानी भट्टाचार्य, आर.के. नारायणन, अरविंद अडिगा द्वारा गांधी जी की विचारधारा पर लिखी गई पुस्तकों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गांधी जी के विचार और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। साहित्य ने समय के साथ-साथ समाज में आये परिवर्तनों को भी दर्शाया है। गांधी जी भारतीय दर्शन और साहित्य में रचे-बसे हैं और इतिहास, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी के प्रयासों के कारण ही देश में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई हैं और वर्तमान में इस भावना को पोषित करने की आवश्यकता है।

सूचना एवं जन संपर्क विभाग के पूर्व निदेशक एवं पी.आर.एस.आई के शिमला चैप्टर के संस्थापक बी.डी. शर्मा ने भी इस अवसर पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि पब्लिक रिलेशन्ज़ सोसायटी ऑफ इंडिया के कुल 25 चैप्टर हैं और शिमला चैप्टर भी इनमें से एक है। उन्होंने अमृत महोत्सव जो पत्रकारिता का अमृत काल भी है, पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि इस दौरान मीडिया कर्मियों की देश के राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता काल में समाचार पत्र-पत्रिकाओं ने देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन के बारे में लिख कर देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत की।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में मीडिया की भूमिका बदल गई है। आज के समय में समाचार पत्रों में सत्यता की कमी चिंता का विषय है। एक समय में पत्रकारिता को मिशन के रूप में अपनाया जाता था लेकिन आज पत्रकारिता एक व्यवसाय बनकर रह गई है। उन्होंने नवोदित पत्रकारों से आहवान किया कि पत्रकारिता की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें।

उन्होंने उपस्थित सभी सहकर्मियों और छात्रों से आहवान किया कि उन्हें पत्रकारिता के विकास के लिए आगे आने की आवश्यकता है। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे देश व प्रदेश का भविष्य हैं और हमारी आशाएं एवं अपेक्षाएं उनसे बंधी हैं।

सूचना एवं जन संपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक तथा पीआरएसआई शिमला चैप्टर के अध्यक्ष प्रदीप कंवर ने सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि पीआरएसआई का शिमला चैप्टर जन संपर्क के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। यह चैप्टर राष्ट्रीय एवं सामाजिक हित के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहा है।

कार्यक्रम से पूर्व, पत्रकारिता के गुरु वेपा राव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लोक संपर्क अधिकारी तथा पीआरएसआई शिमला चैप्टर के महासचिव डॉ. रणवीर वर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इससे पूर्व, छात्रों के लिए परिचर्चा सत्र भी आयोजित किया गया। सूचना एवं जन संपर्क विभाग की अतिरिक्त निदेशक आरती गुप्ता, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के प्रो. डॉ. विकास डोगरा, डॉ. शशिकांत शर्मा और सहायक प्राचार्य डॉ. अजय कुमार तथा पीआरएसआई शिमला चैप्टर के अन्य सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

हिमाचल के मुख्य सचिव आर डी धीमान ने किया "ऑडिट सप्ताह" का उदघाटन

शिमला/शैल। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तत्वावधान में ''ऑडिट सप्ताह'' शिमला स्थित तीनों भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालयों यथा राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी, कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश तथा कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से 21.11.2022 से 27.11.2022 तक मनाया जा रहा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की संस्था के प्रति सामान्य जनता और हितधारकों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सप्ताह भर आउटरीच गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

मुख्य अतिथि आर डी धीमान, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 'ऑडिट सप्ताह' का उदघाटन राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी किया गया। इसके पश्चात मुख्य सचिव द्वारा 'शासन में जवाबदेही' विषय पर पैनल चर्चा की अध्यक्षता की। मनीष कुमार, महानिदेशक, राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी, सुशील कुमार, प्रधान महालेखाकर (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश तथा चंदा एम पंडित, प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। तीनों कार्यालयों के समूह अधिकारी, भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा (2019 बैच), भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी (2021 बैच) तथा वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी भी उदघाटन समारोह में उपस्थित रहे।

पैनल चर्चा में जवाबदेही के विभिन्न पहलुओं यथा, लेखापरीक्षा के क्षितिज का विस्तार,नागरिकों की भूमिका और शासन में डिजटाईजेशन को आच्छादित किया गया। चर्चा में सुशासन के संवर्द्धन हेतु संबन्धित संस्थाओं के लक्ष्यों की जानकारी और विभिन्न जवाबदेही तंत्रों के मध्य निरंतर संपर्क पर भी रोशनी डाली गई ।

भारत के प्रथम महालेखापरीक्षक द्वारा 16 नवम्बर 1860 को कार्यभार संभाला था । इसी दिन की स्मृति में 16 नवम्बर को ऑडिट दिवस मनाया गया। 21-27 नवम्बर को ऑडिट सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न आउटरिच गतिविधियों यथा रक्तदान शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा अभिव्यक्ति (फोटो प्रदर्शनी,गेटी थिएटर) का आयोजन किया जा रहा है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

गुजरात और दिल्ली के चुनावों के परिदृश्य में हिमाचल में जीत का दावा करना बना भाजपा की आवश्यकता

चुनाव समीक्षा के बाद शीर्ष नेताओं के दावों में भिन्नता क्यों
समीक्षा में बीस प्रत्याशी ही जीत के प्रति आश्वस्त हो पाये

शिमला/शैल। मतदान के बाद राजनितिक दल चुनावी समीक्षाओं में व्यस्त हो गये हैं और ऐसा होना स्वभाविक भी है। हिमाचल का हर चुनाव भाजपा कांग्रेस और आप सभी के लिए अलग – अलग महत्व रखता है। इस चुनाव में यदि आप को कुछ मिल जाता है तो इससे उसकी राष्ट्रीय पार्टी बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। लेकिन इसके लिए आप अभी इंतजार कर सकती है और इसीलिए शायद उसने चुनाव के अन्त तक अपनी रणनीति ही बदल ली। भाजपा और कांग्रेस के लिये सीधी लड़ाई का रास्ता साफ कर दिया। भाजपा यदि यह चुनाव हार जाती है तो इसका सीधा प्रभाव हरियाणा पर पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली और पंजाब पहले ही उसके हाथ से निकले हुए हैं। उत्तराखंड में हारे हुए आदमी को उपचुनाव लड़ा कर मुख्यमंत्री बनाना पड़ा है। कांग्रेस की स्थिति भी ऐसी ही है। हिमाचल हारने पर उसके पास पूरे क्षेत्र में पांव रखने के लिए जगह नहीं रहती। कांग्रेस और भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व इस स्थिति को समझता है। इसलिये भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश में लंगर डालकर बैठ गया। प्रधानमंत्री को एक दर्जन रैलियां सम्बोधित करनी पड़ी तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष को परिवार सहित बिलासपुर में डेरा डालना पड़ा। जबकि कांग्रेस ने इस चुनाव में भी स्व. वीरभद्र सिंह के प्रति पनपी सहानुभूति को पूरी तरह भुनाने में कोई कसर नहीं रखी।

इस पृष्ठभूमि में संपन्न हुए प्रदेश के चुनाव में भाजपा चारों उपचुनावों में शून्य होने के तमगे से बाहर ही नहीं निकल पायी। मुख्यमंत्री लाभार्थियों की रैलियों के गणित में ऐसे उलझे की यह भूल ही गये कि हर चीज की एक सीमा होती है। यह सीमाएं लांघने का ही परिणाम था कि प्रधानमंत्री की धर्मशाला की अंतिम रैली बुरी तरह असफल रही। कांग्रेस को जिस स्तर तक तोड़ने की योजना बना रखी थी वह पूरी तरह फेल हो गयी। बल्कि टिकट आवंटन के बाद जिस तरह की बागियों की समस्या से भाजपा को जूझना पड़ा उससे उनके प्रबंधकीय कौशल का भी जनाजा निकल गया। मुख्यमंत्री को यह मानना पड़ा कि एक दर्जन बागी भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतदान के बाद बागियों से संपर्क बनाने के प्रयासों के बयान इसी हताशा का परिणाम है। इसलिये बागियों को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ब्यान अन्त विरोधी होकर सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री बागियों से संपर्क में होने की बात कर रहे हैं तो प्रदेश प्रभारी बागियों के बिना ही अपने दम पर सरकार बनाने की बातें कर रहे हैं। शीर्ष नेताओं के परस्पर भिन्न ब्यानों से ही स्पष्ट हो जाता है कि परिणामों को लेकर सबकी एक राय नहीं है।

यह चुनाव पार्टी की नीतियों पर न होकर सरकार की पांच वर्ष की कारगुजारी पर हुए हैं। सरकार को पांच वर्षो में सात मुख्य सचिव क्यों बनाने पड़े इस सवाल का जवाब अन्त तक नहीं आया है। इस सवाल पर सरकार और संगठन में पांच वर्षो में कोई जुबान नहीं खोल पाया है कि लोकसेवा आयोग में जनवरी 2018 में की गयी नियुक्ति कार्यकाल के अन्त तक गले की हड्डी क्यों बनी रही? सरकार के इन कदमों का प्रशासनिक कुशलता पर ऐसा कुप्रभाव पड़ा जो अन्त तक सूलझ ही नहीं पाया। इस परिदृश्य में हुई चुनावी समीक्षा में कोई कितनी सपष्टता से अपनी बात रख पाया होगा इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। वैसे सूत्रों के मुताबिक इस समीक्षा में भी बीस से अधिक प्रत्याशी अपनी जीत का भरोसा नहीं दिला पाये हैं। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि अन्त में व्यवहारिक स्थिति क्या रहने वाली है। वैसे तो अभी गुजरात और दिल्ली एम सी डी के चुनावों के परिपेक्ष में यह दावा करना राजनीतिक आवश्यकता बन जाता है कि हिमाचल में भाजपा सत्ता में वापसी कर रही है। क्योंकि हिमाचल के अधिकांश नेताओं की दिल्ली में चुनाव प्रचार में जिम्मेदारियां लगी हुई हैं। इन प्रचार में जिम्मेदारियों के कारण हिमाचल में जीत का दावा करना राजनीतिक आवश्यकता बन जाता है।

अमन काचरू की मौत के जिम्मेदारों को दी जयराम सरकार ने नौकरी

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने 21.7.2022 को 106 डॉक्टरों को Stop Gap Arrangement के नाम पर दो वर्ष के लिये नियुक्तियां दी हैं। इन नियुक्तियों में डॉ. अभिनव वर्मा, डॉ.नवीन कुमार और डॉ. मुकुल शर्मा के नाम भी शामिल हैं। स्मरणीय है कि यह तीनों लोग डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में घटे अमन काचरू रैगिंग प्रकरण में शामिल थे। इसमें अमन काचरू की मौत हो गयी थी। इस मौत के बाद इन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने इन्हें हत्या का दोषी पाया और चार लोगों को सजा सुनायी। इस सजा के खिलाफ यह चारों लोग नवीन कुमार, अभिनव वर्मा, अजय वर्मा और मुकुल शर्मा 2010 में अपील में चले गये। इस अपील में उच्च न्यायालय ने इनकी और सरकार की अपीलों को खारिज करते हुए 4 अप्रैल 2013 को दिये अपने फैसले में सजा को बरकरार रखते हुये यह फैसला दिया।

In so far as sentence is concerned, we observe that a young medical student had died consequent upon violent and repeated slapping by the accused persons which is inhuman and is a blatant breach of human right. The victim was the only son of his parents. His life has gone for a song. The accused persons were also medical students which is considered to be a cream, but their barbarous act was a dastardly act for a youth who was none else than their college-mate. While balancing all the factors of both the sides we do feel that it is absolutely not a case of giving any benefit under the benefit of Probation of Offenders Act. However, in the totality of facts and circumstances and looking at the punishment provided for the offences for which they have been held guilty and by adopting a balanced approach to meet the ends of justice, we affirm the sentence already imposed by the learned trial court, with modification in sentence that in addition to the fine already imposed, each of the accused appellants shall also deposit compensation to the tune of `1,00,000/- each under section 357 Cr.P.C. within a month from today, failing which it shall be realized by the learned trial court as a fine. The amount so realized shall be released to the next of the kin of deceased Aman Kachroo. To the above extent, the sentence stands modified. We also feel that the life of deceased cannot be compensated in money but at the same time the accused persons should also realize that they have been sufficiently atoned for their misadventure.

56. In view of the above analysis, discussion, in substance Criminal Appeals No.519, 552, 553 of 2010 and Criminal Appeal No.17 of 2011, are dismissed and also Criminal Appeals No.48 and 80 of 2011, preferred by the State under Section 377 and 378 respectively of the Code of Criminal Procedure are also dismissed.

इस फैसले के अनुसार यह दोषी पाये गये और इन्होंने सजा भोगी है। कानून के जानकारों के मुताबिक जब कोई सजा भोग लेता है तब सरकारी नौकरी आदि पाने के उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। यह लोग भी सजा भोगने के बाद उसी श्रेणी में आ जाते हैं। सरकारी नौकरी पाने का इनका अधिकार प्रश्नित हो जाता है। स्मरणीय है कि जब यह मामला बना था तब इनकी पढ़ाई जारी रखने पर भी सवालिया निशान लग गया था। तब यह राय बनी थी कि अदालत ने इन्हें सजा दी है लेकिन इनके पढ़ाई करने का अवसर दिया गया था। अब यह पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर बन गये हैं। डॉक्टर होने के कारण ही बतौर डॉक्टर नौकरी दी गयी है। लेकिन इनकी सजा के कारण इनके नौकरी पाने के अधिकार पर सवाल उठने शुरू हो गये हैं।

ऐसे में यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि इनके सजाभोगी होने के बावजूद इन्हें सरकार ने नौकरी कैसे दे दी? क्या नौकरी देने के समय इनके रिकॉर्ड को नहीं देखा गया? क्या सरकार ने इसमें नियमों में कोई विशेष छूट दी है या नौकरी देने के समय इनका यह रिकॉर्ड प्रशासन के सामने आ ही नहीं पाया है। लेकिन यह नौकरी मिलने के बाद एक नयी बहस अवश्य शुरू हो गयी है।